आजाद रहिये
विचारों से
लेकिन बंधे रहिये
संस्कारों से।
– अज्ञात

सुरक्षा के कारगर तरीके

दिलचस्प यह है कि यूरोपीय देशों में स्वीडन इकलौता ऐसा देश है जिसने लॉकडाउन लागू नहीं किया है। उसने सोशल डिस्टेंसिंग, बार–बार हाथ धोने और लगातार सैनिटाइजेशन पर जोर दिया। भारत को जल्द–से–जल्द बढ़ी हुई मृत्यु दर के बारे में विश्लेषण करना चाहिए।

स्वामिनाथन एस. अंकलेसरिया अय्यर।

कोरोना के दौरान शटडाउन का दुनिया भर में सबसे बड़ा सबक यह रहा कि इस दौरान कोरोना वायरस से जितने लोग मारे गए, लगभग उतने ही लॉकडाउन के कारण अपनी जान गंवा बैठे। कोरोना के इलाज का जो तरीका है, वह बीमारी के बराबर ही बुरा है।

फाइनैंशल टाइम्स, लंदन के मुताबिक अधिकतर देशों में मार्च और अप्रैल के महीने में मृत्यु दर पिछले पांच बरसों के मुकाबले ज्यादा थी, खासकर यूरोपीय देशों में। आंकड़ों के मुताबिक सामान्य मृत्यु दर के मुकाबले यह आंकड़ा 49 फीसदी ज्यादा था। लेकिन इसमें से बमुश्किल आधी मौतें कोरोना की वजह से हुई थीं। इनमें भी गैर–कोरोना मौतों के आंकड़ों में शायद कई मौतें ऐसी भी थीं, जिनमें कोरोना का पता नहीं चल पाया। ऐसे ज्यादातर लोग लॉकडाउन के साइड–इफेक्ट्स के कारण मारे गए। इससे क्या सीख मिलती है? यही कि भारत को लॉकडाउन जल्दी–से–जल्दी खत्म कर देना चाहिए। हां, हमें ऐहतियात जरूर बरतनी चाहिए। सुरक्षा के कारगर तरीके ढूंढने चाहिए और आर्थिक गतिविधियां चालू कर देनी चाहिए।

बढ़ी हुई मृत्यु दर की बात करें तो बेल्जियम में यह आंकड़ा 60 फीसदी, नीदरलैंड में 51 फीसदी लेकिन स्वीडन में सिर्फ 12 फीसदी ही था। दिलचस्प यह है कि यूरोपीय देशों में स्वीडन इकलौता ऐसा देश है जिसने लॉकडाउन लागू नहीं किया है। उसने सोशल डिस्टेंसिंग, बार–बार हाथ धोने और लगातार सैनिटाइजेशन पर जोर दिया। इससे यह संकेत मिलता है कि दुनिया में सबसे सख्त तरीके से लॉकडाउन लगाने वाले भारत ने शायद लोगों की जिंदगी को बचाए बगैर अर्थव्यवस्था की हत्या कर दी क्योंकि लॉकडाउन के कारण कोरोना मौतों में कमी लॉकडाउन की वजह से होने वाली ज्यादा मौतों का मुकाबला नहीं कर पाती है। भारत को जल्द–से–जल्द बढ़ी हुई मृत्यु दर के बारे में विश्लेषण करना चाहिए। यह मृत्यु दर महानगर केंद्रित है 1,500 फीसदी जर्काता में, 299 फीसदी न्यू यॉर्क में और 96 फीसदी लंदन में। डॉक्टरों का कहना है कि दिल की बीमारी, स्ट्रोक, कैंसर जैसी दूसरी बीमारियों के मरीजों के अस्पताल में आने की संख्या अभी काफी कम हो गई है। लक्षण होने के बावजूद लोग अस्पताल जाने से बच रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अस्पताल जाने पर कहीं कोरोना न हो जाए। पूरा का पूरा मेडिकल तंत्र कोरोना के खिलाफ लड़ाई में इस कदर जुट गया है कि दूसरी बीमारियां नजरअंदाज हो गई हैं। गैर–जरूरी सभी सर्जरी रोक दी गई हैं, आईसीयू के अधिकतर बेड कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व रख कर दिए गए हैं।

कोरोना को रोकने की इस कोशिश में दूसरी वजहों से मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। ब्रिटेन के कैंसर रिसर्च इंस्टिट्यूट के अनुसार जांच के लिए अस्पताल जाने वाले कैंसर के संभावित मरीजों की तादाद अचानक काफी कम हो गई है। अनुमान है कि हर हफ्ते कैंसर के करीब 2000 मामले नजरअंदाज हो रहे हैं। इनमें से 400 महज इसलिए पकड़ में नहीं आ रहे क्योंकि ब्रेस्ट और पेट के कैंसर की साधारण जांच फिलहाल बंद कर दी गई है।

समर्पण की पृष्ठभूमि

धर्म-दर्शन

अशोक वोहरा। कुछ यहीं से आरंभ होती है भरत की द्वंदात्मिका, वेदना की श्रृंखला, निश्चयात्मक समर्पण की पृष्ठभूमि..... माँ के पुत्रमोह के अतिरेक का आतंक स्वयं अपनी आँखों से देख भरत हृदय की गहराइयों तक विदीर्ण हो चुके हैं। बोधरहित निश्चेष्ट शरीर शैथिल्यमान है। एकटक दीवारों को निहारते भरत भविष्य की चिंता में डूब जाते हैं। उनके समक्ष यक्षप्रश्न उपस्थित है कि जिस ज्येष्ठ को वे निष्कलुष स्नेह करते हैं, जिसके लिए वो समस्त संसार का परित्याग सहर्ष कर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें तत्क्षण प्राण त्यागने में किंचित मात्र विलंब नहीं हो सकता, उन श्रीराम के समक्ष उनका प्रेम कैसे प्रमाणित होगा। दुविधा से ग्रस्त भरत इस ख्याल में हैं कि जगत में उनकी भ्रातृ भक्ति कलंकित हो गई है, वो कैसे सिद्ध करें कि उन्हें राज्याधिकार नहीं चाहिए जबकि उनके लिए त्रिलोक स्वामी भी बनना श्रीराम के प्रेम के समक्ष त्याज्य है।

संपादकीय

सबसे बड़ी गिरावट

हमारे देश में प्राइवेट अस्पतालों का मानना है कि लॉकडाउन के कारण सर्जरी और ओपीडी में आने वाले मरीजों की संख्या पूरी तरह से कम हो गई है। आईसीयू में बेड खाली पड़े हैं और पैसे का जबरदस्त नुकसान हो रहा है। काम चालू रखने और कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए अस्पतालों को सरकार से वित्तीय मदद की दरकार है। भारत में हर साल टीबी के 2.50 करोड़ मामले सामने आते हैं जिनमें से 4.40 लाख की हर साल मौत हो जाती है। भारत में हर साल मलेरिया के 20 लाख मामले पता चलते हैं, जिनमें से 20 हजार की मौत हो जाती है। लॉकडाउन के कारण लगभग हर राज्य में एंटी–मलेरिया अभियान रोक दिया गया है। ऐसे में कोरोना से होने वाली कुछ एक हजार मौतें दूसरी बीमारियों से होने वाले कुल मौतों के मुकाबले कहीं कम हैं।

लॉकडाउन ने ट्रैफिक और वर्कप्लेस पर होने वाली मौतों को अच्छी–खासी संख्या में कम किया है। अपराधी घरों में बंद हैं इसलिए हत्याएं कम हो रही हैं। इन सब वजहों से गैर–कोरोना मौतें बेहद कम होनी चाहिए थीं लेकिन लॉकडाउन में हुआ उलटा है। येल यूनिवर्सिटी की एक स्टडी के मुताबिक इस बार मार्च की शुरुआत से लेकर 4 अप्रैल तक अमेरिका में 15,400 मौतें सामान्य से ज्यादा हुईं। इन ज्यादा मौतों में कोरोना का योगदान 53 फीसदी थ। इसमें सबसे ज्यादा मौतें मिशिगन में 77 फीसदी, जबकि मेरीलैंड में सबसे कम 18 फीसदी थीं।

आंकड़ा विशेषज्ञ प्रणब सेन सही ही कहते हैं कि भारत को न सिर्फ जिंदगी बल्कि कारोबार को भी बचाना चाहिए। कारोबार ही लोगों को रोजगार देता है। भारत में उत्पादन करने वाली आधी क्षमता लॉकडाउन में बंद है। भारत भी उसी रास्ते पर है। महामंदी के बाद यह सबसे बड़ी गिरावट है।

अगर सिसोदिया का यह प्रस्ताव मानव संसाधन विकास मंत्रालय मान लेता है तो खासकर 12वीं के अधर में लटके छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी।

एक महत्वपूर्ण सुझाव

रेखा शर्मा।

दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अधूरी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया है, जिस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षाएं कराना अब संभव नहीं हो पाएगा, लिहाजा इंटरनल एग्जाम्स के आधार पर ही बच्चों को पास किया जाए, जैसा 9वीं और 11वीं के बच्चों के साथ किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि अगले वर्ष के लिए समूचे पाठ्यक्रम में कम से कम 30 फीसदी की कमी की जाए और जेईई, नीट तथा अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों की प्रवेश परीक्षाएं भी इस कम किए गए पाठ्यक्रम के आधार पर ही ली जाएं। अगर सिसोदिया का यह प्रस्ताव मानव संसाधन विकास मंत्रालय मान लेता है तो खासकर 12वीं के अधर में लटके छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी। दरअसल, कोरोना संकट ने पढ़ाई–लिखाई और परीक्षाओं की पूरी लय ही बिगाड़ दी है। भारत में कोरोना के कारण लॉकडाउन का फैसला तब किया गया जब परीक्षाएं अपने अंतिम दौर में थीं।

लॉकडाउन के कारण बचे हुए कुछ पेपर्स स्थगित करने पड़े। अब चूंकि लॉकडाउन हटने

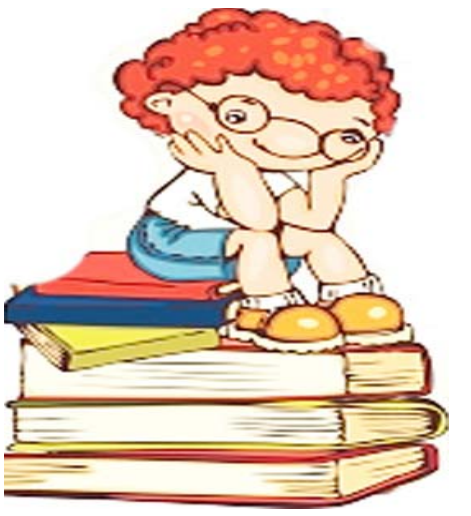

की तिथि को लेकर कुछ भी निश्चित नहीं है इसलिए परीक्षाओं का मामला भी अनिश्चित बना हुआ है। कभी कहा जा रहा है कि परीक्षाएं ली जाएंगी तो कभी यह कि बचे हुए विषयों में औसत अंक दे दिए जाएंगे। बीच में यह चर्चा भी चली कि बची हुई परीक्षाएं ऑनलाइन ली जाएंगी।

इस दुविधा से बच्चे बहुत परेशान हैं। वे समझ नहीं पा रहे कि वे इन विषयों की अपनी तैयारी जारी रखें या इस दबाव से मुक्त होकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी पर फोकस करें। अभी जो हालात हैं, उनमें सरकार भी उन्हें कोई आश्वासन देने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि स्थितियां कब सामान्य होंगी, कोई नहीं जानता। इस बीच पिछले सेशन का समय समाप्त हो चला है, लिहाजा बेहतर यही होगा कि परीक्षा न ली जाए और आंतरिक परीक्षा के आधार पर नंबर दे दिए जाएं। इस तरह के किसी फैसले तक पहुंचने में और देर करना ठीक नहीं है।

दसवीं–बारहवीं में पढ़ने वाले बच्चों का मन कुछ ज्यादा ही संवेदनशील होता है। छोटी–छोटी बातें भी इस उम्र में उन्हें बहुत प्रभावित करती हैं। वे इस समय अपने भविष्य को लेकर काफी चिंतित रहते हैं। ज्यादा लंबी अनिश्चितता उनके मन–मस्तिष्क पर गलत प्रभाव डाल सकती है। वैसे भी मौजूदा संकट से बच्चे बहुत परेशान हैं। अर्थव्यवस्था और रोजी– रोजगार के क्षेत्र से आ रही नकारात्मक खबरें उन्हें निराश कर रही हैं। मान लिया जाए कि कुछ दिनों में हालात सुधर गए तो भी लंबे समय तक खाली बैठने के बाद अचानक फिर से परीक्षा देने में वे सहज नहीं महसूस कर पाएंगे। सिलेबस में ढील देने का सुझाव भी बेहद अहम है। विपरीत परिस्थितियों में पैदा मानसिक दबाव को देखते हुए स्टूडेंट्स को थोड़ी राहत जरूर दी जानी चाहिए। आशा है कि सरकार और बोर्ड इस बारे में जल्दी कोई निर्णय करेंगे।

सूडोकु नवताल-5340

सरल

2		8	5	1	9	6		7
					8			1
		7	4	6		8		9
3	2				7			8
1		9		4		7		5
4			2				9	3
6		3		5	1	9		
8			3					
7		1	9	2	6	3		4

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं.
- प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.
- पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते.
- पहेली का केवल एक ही हल है.

सूडोकु नवताल -5339 का हल

7	1	9	8	5	3	2	6	4
4	5	3	6	2	9	7	1	8
6	2	8	4	7	1	9	5	3
9	8	2	7	3	5	1	4	6
1	3	6	9	4	8	5	7	2
5	7	4	1	6	2	8	3	9
8	4	7	5	9	6	3	2	1
3	6	1	2	8	7	4	9	5
2	9	5	3	1	4	6	8	7

Jagrutidaur.com, Bangalore

अपना ब्लॉग

सरकारी आमदनी सीमित

मोहन। दुनिया भर का अनुभव यही कहता है कि भारत को अपने लोगों और कारोबार को बचाने के लिए खुला खर्च करना चाहिए। जापान अपनी जीडीपी में से इसके लिए अतिरिक्त 20 फीसदी खर्च कर रहा है। अमेरिका ने जो पहला पैकेज जारी किया है, उसमें यह आंकड़ा जीडीपी का 10 फीसदी है, दूसरे पैकेज में 6 प्रतिशत और मिल सकता है। भारत ने फिलहाल जिस राहत पैकेज का ऐलान किया है, वह जीडीपी के एक फीसदी से भी कम है। इसे पांच गुना बढ़ाए जाने की जरूरत है। चूंकि सरकारी आमदनी सीमित है, टैक्स से मिलने वाली आमदनी में भी कमी होगी इसलिए आरबीआई को जीडीपी की कम–से–कम 5 फीसदी रकम के रुपये छापने चाहिए ताकि लोगों की जिंदगी और कारोबार को बचाने में इसे खर्च किया जा सके। कुछ अर्थशास्त्रियों को डर है कि इससे महंगाई में इजाफा होगा लेकिन दूसरे देशों में जब ऐसी कोशिश हुई थी तो उससे कीमतों में बढ़ोतरी नहीं हुई। ऐसे में इस हालत में जान फूंकने के लिए आर्थिक गतिविधियों को फिर से बहाल करना जरूरी है।